>

Title: Need to provide adequate quantity of foodgrains, kerosene and other essential commodities to Himachal Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को आबंटित किए जाने वाले खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल एवम् अन्य आवश्यक वस्तुओं का जो कोटा निर्धारित था, उससे बहुत कम प्रदान किया जा रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 16,02,931 ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवम् ए.ए.वाई. परिवारों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दो वर्ष पूर्व ए.पी.एल. का चावल कोटा 9860 मीट्रिक टन निर्धारित था, जिसे शून्य कर दिया गया और विशेष अनुरोध के बाद केवल 7118 मीट्रिक टन चावल दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 10.88 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जबकि भारत सरकार केवल 7.43 लाख राशन कार्डों के लिए प्रदेश को चावल का कोटा आबंटित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 5411 किलोलीटर केरोसिन तेल की खपत है, लेकिन वर्ष 2010-2011 में केवल 3352 किलोलीटर केरोसिन तेल का कोटा निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ों एवम् ऊंची-ऊंची पर्वत शृंखलाओं में बसा है। जंगलों की रक्षा करनी है, तो प्रदेश के लिए केरोसिन तेल और एल.पी.जी. की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अतः अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश को दिए जाने वाले खाद्यान्न एवम् मिट्टी के तेल का कोटा यदि बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो उसे कम न किया जाए।